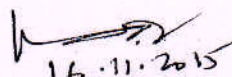


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या1736 / 2015.....जिला.....भरतपुर.....

उनवान – मैसर्स तरुण एण्ड कम्पनी, नई मण्डी, भरतपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त बी भरतपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.11.2015	<p>कैम्प जयपुर एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 3,06,025/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है।</p> <p>अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज घीया एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद की बहस सुनी गई।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशिरूपये 3,06,025/- की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>8. आदेश प्रसारित किया गया।</p>	


 16.11.2015
 (मदन लाल)